

अनु०-13 :- मूल अधिकार के असंगत विधि :-

⇓
✓ गृहण या अच्छादन का सिद्धान्त :-

1. - मूल अधिकार के शक्तियों से कमी करने का अधिकार संसद के पास नहीं है।
2. :- यदि भारत के नागरिक है, तो मूल अधिकार का परित्याग नहीं कर सकते।

* सरकार के द्वारा ऐसी किसी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा, जिससे कि मूल अधिकार का अल्पिकरण होता हो। यदि ऐसी कोई विधि बनायी जाती है, तो वह विधि प्रभावहीन या शून्य होगा।

लोकसभा मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

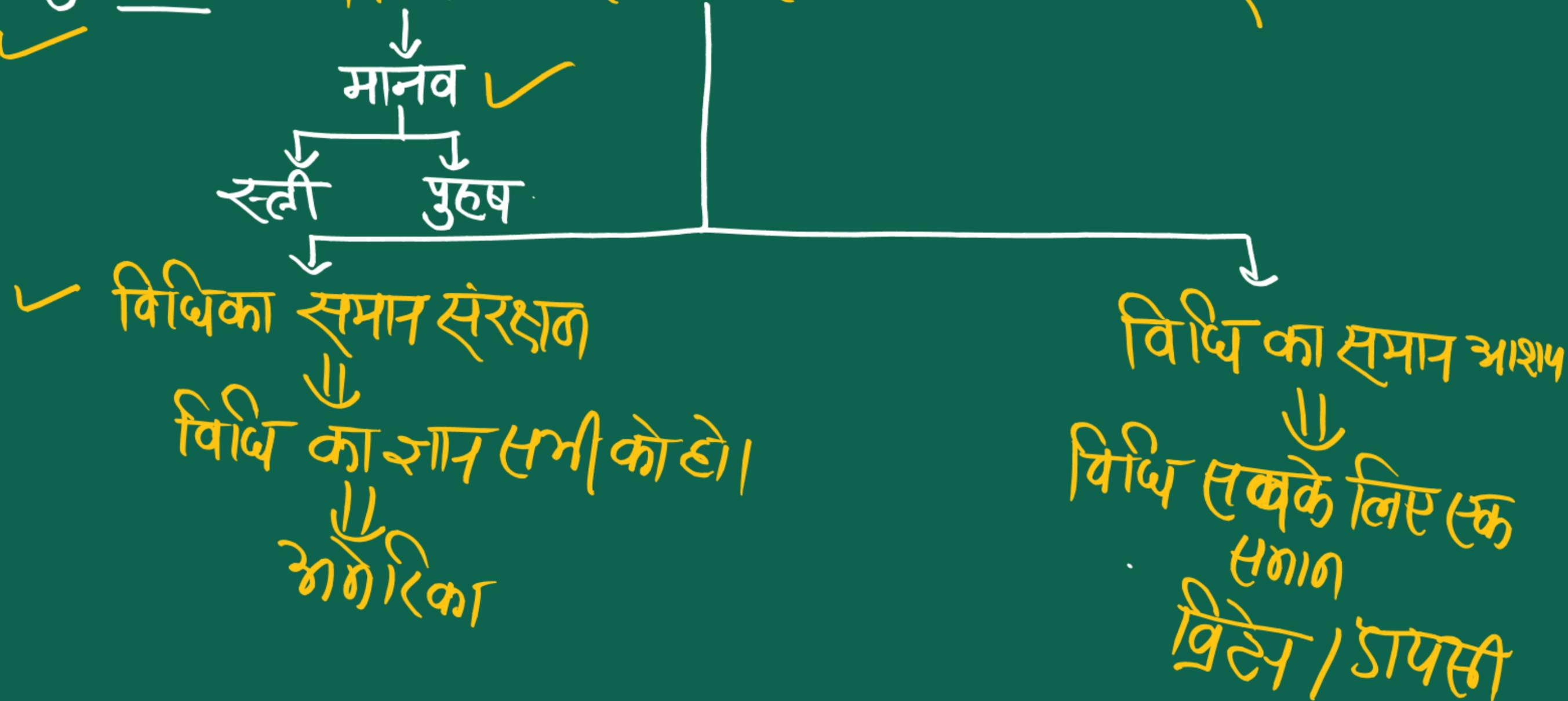
⇒ संसद, विधान मण्डल, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी कागुन को उच्चतम न्यायापालिका लागू करने से रोक सकेगा।

अनु-32

HC-अनु-32क.

① समता या समानता का अधिकार - अनु०-14-18.

अनु०-14 - विधि के समक्ष समता का अधिकार



अपवाद:- राज्यपाल, राष्ट्रपति तथा राजनौपिक पर

↳ संसद सदस्य पर विधि की अलग है - (अड-105)

अनु-15:- समाजिक न्याय-

Social Justice:-

जाति, धर्म, लिंग, वंश व
जन्म स्थान के आधार पर किसी
व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं
किया जायेगा।

- Ex:- 2018 से पहले सुवरी माला मन्दिर
केरल
भयव्यासजी

15- 1- राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ भेद-भाव नहीं किया जाएगा।

2- किसी भी सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से राज्य सरकार रोक नहीं लगा सकता।

→ सामुदायिक, तालाब, कुड्यौं, मन्दिर, विद्यालय
अस्पताल, होटल- आदि।

3- राज्य महिलाओं, और बच्चों के उत्थान के लिए कार्य करेगा।

4- शिशु और महिलाओं शैक्षणिक और सामाजिक हक से पिछड़े रहे
हो, राज्य प्रवर्ध

अनु-16 :- लोक नियोजन में समानता :-

↓
सरकारी नौकरी

→ सरकारी नौकरियों में जाते

धर्म, लिंग वंश व जन्मस्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जायेगा।

अनु-16-D :- नौकरियों में आरक्षण :-

SC/ST/OBC व महिलामें को नौकरियों में

आरक्षण का प्रावधान है।

103-C.A.M-2018-19-एवमों के लिए आर्थिक आधार पर 10% नौकरी के

आरक्षण प्रावध

भारतीय
Criminal Law

OBC-मॉडल

UP सिं 1979

1989

1990 → 10%

Gen - <u>80%</u>	<u>20%</u>	→ <u>अधिकार</u>
OBC - <u>20%</u>	<u>80%</u>	
SC/ST - <u> </u>	<u>100%</u>	

1993

अठ-17 - अस्पृश्यता का अन्त - \Rightarrow गाँधी दर्शन का प्रभाव है।
इआ-इत

व्यक्ति के
विषय व्यक्ति की
अधिकार है।

इआ-इत के निवारण के लिए, ① शिक्षा ② कानून.

③ जनजागरण आवश्यक है।

यदि इआ इत को किसी भी रूप में वापस दिया जाता है
तो विधि द्वारा दण्डित किया जाएगा।

अस्पृश्यता निवारण अधि, 1955 \rightarrow लोक परिवर्तन - समाज नागरिक

अधिकार संरक्षण अधि, 1976

SC/ST Act - 1989